

## प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023

### प्रलिस के लिये:

प्रेस और पुस्तकों का रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867, मेटकाफ अधिनियम, जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसिंग विनियम।

### मेन्स के लिये:

भारत में प्रेस विनियमन, प्रेस की मुख्य विशेषताएँ और नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023

[स्रोत: पी.आई.बी.](#)

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में लोकसभा ने [प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1867](#) के औपनिवेशिक युग के कानून को नरिस्त करते हुए प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 पारित किया।

- यह अधिनियम अगस्त 2023 में राज्यसभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है।

## प्रेस, नयितकालिक पत्रिका रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

- पत्रिकाओं का रजिस्ट्रीकरण:** यह अधिनियम पत्रिकाओं के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है, जिसमें सार्वजनिक समाचार या सार्वजनिक समाचार पर टिप्पणियों वाला कोई भी प्रकाशन शामिल है।
  - पत्रिकाओं में **कतिबेँ या वजिज्ञान से संबंधित** और **अकादमिक पत्रिकाएँ** शामिल नहीं हैं।
    - जबकि अधिनियम समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों के रजिस्ट्रीकरण का प्रावधान करता है। इसने पुस्तकों की सूचीकरण की भी व्यवस्था की।
  - पुस्तकों को अधिनियम के दायरे से बाहर कर दिया गया है, क्योंकि एक विषय के रूप में पुस्तकों का प्रबंधनमानव संसाधन और विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
- प्रकाशनों हेतु रजिस्ट्रीकरण प्रोटोकॉल:** अधिनियम प्रकाशकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल और नरिदष्टि स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण करने में सक्षम बनाता है।
  - इसके अलावा **आतंकवाद या राज्य सुरक्षा** के खिलाफ कार्रवाई के दोषी व्यक्तियों के लिये किसी पत्रिका का प्रकाशन नषिदिध है।
  - जबकि अधिनियम में **ज़िला मजिस्ट्रेट को एक घोषणा पत्र देना अनविवार्य था**, जसि इसे समाचार पत्र प्रकाशन के लिये प्रेस रजिस्ट्रार के पास भेजना था।
- वदिशी पत्रिकाएँ:** भारत के भीतर वदिशी पत्रिकाओं के मुद्रण के लिये **केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन** की आवश्यकता होती है। ऐसी पत्रिकाओं के पंजीयन के लिये वशिष्ट प्रोटोकॉल की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
- प्रेस महा-रजिस्ट्रार:** यह अधिनियम **भारत के प्रेस महा-रजिस्ट्रार** की भूमिका की व्याख्या करता है, जो सभी पत्रिकाओं के लिये रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने हेतु उत्तरदायी है।
  - इसके अतिरिक्त उसके कर्तव्यों में **पत्र-पत्रिकाओं के रजिस्ट्रार बनाए रखना, पत्र-पत्रिकाओं के शीर्षकों के लिये दशिा-नरिदेश स्थापित करना, परिचालन आँकड़ों की पुष्टि करना तथा रजिस्ट्रीकरण संशोधन**, नलिबन एवं रददीकरण का प्रबंधन करना शामिल है।
- मुद्रण प्रेस रजिस्ट्रीकरण:** प्रदिगि प्रेस से संबंधित घोषणाएँ अब **ज़िला मजिस्ट्रेट** के समक्ष की गई घोषणाओं की आवश्यकता से हटकर **प्रेस महारजिस्ट्रार** को ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं।
- रजिस्ट्रीकरण का नलिबन तथा रदद करना:** प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के पास भ्रामक सूचना प्रस्तुत करने, प्रकाशन में रुकावट अथवा अनुचित वार्षिक ववरण प्रदान करने सहित विभिन्न कारणों से किसी पत्रिका के रजिस्ट्रीकरण को **न्यूनतम 30 दिनों (180 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है) के लिये नलिबत करने का अधिकार है**।
  - इन मुददों को हाल करने में वफिलता के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकरण रदद किया जा सकता है।
  - रदद करने के अन्य आधारों में **अन्य पत्रिकाओं के साथ शीर्षकों की समानता** अथवा स्वामी/प्रकाशक द्वारा **आतंकवाद अथवा राष्ट्रीय सुरक्षा के वरिद्ध कृत्यों** से संबंधित दोषसदिधि शामिल है।

- **दंड और अपील:** यह वधियक महारजसिद्दार को **अपजीकृत पत्र-पत्रिका प्रकाशन** अथवा नरिदषिट समय-सीमा के भीतर वार्षिक वविरण प्रसुतुत करने में वफिलता के लयि **जुरमाना लगाने का अधकिार** देता है।
  - इन नरिदेशों का पालन न करने पर **छह महीने** तक की कैद हो सकती है।
  - इसके अतरिकित रजसिद्रीकरण प्रमाणपत्रों को असवीकार करने, रजसिद्रीकरण के नलिबन/रददीकरण अथवा लगाए गए दंड के वरिद्ध अपील के प्रावधान **प्रेस और रजसिद्रीकरण अपीलीय बोरुड के समकष अपील दायर करने के लयि 60 दनिों की अवधि** के साथ उपलब्ध है।

## प्रेस वनियमन से संबंधति अन्य स्वतंत्रता-पूर्व कानून क्या हैं?

- **लॉर्ड वेलेज़ली (वर्ष 1799) के तहत सेंसरशपि:** फ्रँसीसी आक्रमण की आशंकाओं के कारण पूर्व-सेंसरशपि सहति सख्त युद्धकालीन प्रेस नयितरण लागू कयिा गया।
  - बाद में सन् 1818 में **लॉर्ड हेस्टिंग्स** द्वारा प्री-सेंसरशपि हटाकर इसमें ढील/छूट दी गई।
- **जॉन एडम्स द्वारा लाइसेंसि वनियम (1823):** बनिा लाइसेंस के प्रेस शुरु करने या संचालति करने के लयि दंड का प्रावधान कयिा गया, जसिे बाद में बढ़ाते हुए वभिनिन प्रकाशनों पर लागू कर दयिा गया।
  - मुख्य रूप से भारतीय भाषा के समाचार पत्रों या भारतीयों के नेतृत्व वाले समाचार पत्रों को नशिाना बनाया गया, जसिके कारण **राममोहन राय का मरिात-उल-अकबर** बंद हो गया।
- **प्रेस अधनियम, 1835 (मेटकाफ अधनियम):** प्रतबिंधात्मक 1823 अध्यादेश को नरिसुत कर दयिा गया, जसिसे मेटकाफ को "भारतीय प्रेस के मुकुतदािता" की उपाधी मिली।
  - मुद्रकों/प्रकाशकों द्वारा अपने परसिर के बारे में सटीक घोषणाएँ करना अनविरय की गई और आवश्यकतानुसार समापुतकी अनुमति दी गई।
- **वर्ष 1857 के वदिरोह के दौरान लाइसेंसि अधनियम:** 1857 के आपातकाल के कारण आगे लाइसेंसि प्रतबिंध लगाए गए।
  - मौजूदा रजसिद्रीकरण प्रकरयिाओं को संवरद्धति कयिा गया, जसिसे सरकार को कसिी भी मुद्रति सामग्री के प्रसार को रोकने की शकुती मलि गई।
- **वर्नाक्यूलर प्रेस अधनियम, 1878:** इसे वर्नाक्यूलर प्रेस को वनियमति करने, राजद्रोह से संबंधति लेखन को प्रतबिंधति करने और वभिनिन समुदायों के बीच कलह को रोकने के लयि उजिाइन कयिा गया।
  - स्थानीय समाचार पत्रों के मुद्रकों और प्रकाशकों को **सरकार वरिेधी या वभिजनकारी वषियों** का प्रसार करने से परहेज के लयि एक बॉण्ड पर हसुताकषर करने की मांग की गई।
  - मजसिद्रेट द्वारा लयि गए नरिणय न्यायालय में अपील के कसिी भी अवसर के बनिा अंतमि होते थे।
- **समाचार पत्र (अपराधों को उकसाना) अधनियम, 1908:** हसिा या हत्या को उकसाने, आपततजिनक वषिय-वसुतुओं को प्रकाशति करने वाली प्रेस संपततयिों को ज़बुत करने के लयि मजसिद्रेटों को अधकिार दयिा गया।
  - **उग्र राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तलिक को राजद्रोह के आरोपों का सामना करना पड़ा** और उन्हें मांडले ले जाया गया, जसिसे व्यापक वरिेध और हड़ताल के घटनाएँ हुईं।
- **भारतीय प्रेस अधनियम, 1910:** स्थानीय सरकार रजसिद्रीकरण के समय सुरक्षा की मांग कर सकती थी, उल्लंघन करने वाले समाचार पत्रों को दंडति कर सकती थी और जाँच के लयि नशिुलक प्रतयिों की मांग कर सकती थी।
  - वर्नाक्यूलर प्रेस अधनियम के समान कड़े नयिम लागू करके प्रेस की स्वतंत्रता को बाधति कयिा गया।

## बाल-वविाह समापुत करने की दशिा में प्रगति

### प्रलिमिस के लयि:

[सतत विकास लकष्य 5.3](#), [UNICEF](#), [बाल-वविाह प्रतषिध अधनियम, 2006](#), बाल वविाह नषिध अधकिारी, धनलकष्मी योजना

### मेन्स के लयि:

बाल वविाह से संबंधति प्रमुख कारक, वधिायी ढाँचा और भारत में बाल वविाह की रोकथाम से संबंधति पहल

## स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

## चरचा में क्यो?

'द लैसेट ग्लोबल हेल्थ' जर्नल में प्रकाशति एक हालयिा अध्ययन **भारत में बाल-वविाह** की मौजूदा स्थति को उजागर करता है, जसिसे समाज में गहनता से व्यापुत इस कुप्रथा के खलिाफ लड़ाई में प्रगति तथा वफिलता दोनों का पता चलता है।

## अध्ययन में उजागर प्रमुख रुझान क्या हैं?

### ■ भारत में स्थिति:

- वर्ष 1993 में बाल-ववाह के मामले 49% थे जो वर्ष 2021 में घटकर 22% हो गए। बालकों के बाल-ववाह के मामले वर्ष 2006 में 7% थे जो वर्ष 2021 में घटकर 2% हो गए, यह राष्ट्रीय स्तर पर समग्र गतिवृत्त का संकेत देता है।
  - हालाँकि वर्ष 2016 से 2021 के बीच यह प्रगति धीमी हो गई तथा कुछ राज्यों में बाल-ववाह में चिंताजनक वृद्धि हुई।
  - विशेष रूप से छह राज्यों में बालिका बाल-ववाह में वृद्धि देखी गई, जिनमें मणिपुर, पंजाब, त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
  - छत्तीसगढ़, गोवा, मणिपुर तथा पंजाब सहित आठ राज्यों में बालकों के बाल-ववाह में वृद्धि देखी गई।
- वैश्विक रुझान: विश्व स्तर पर बाल-ववाह के विरुद्ध हुई प्रगति उल्लेखनीय रही है कति **कोविड-19 महामारी** ने इस प्रगति को खतरे में डाल दिया, जिससे एक दशक में लगभग 10 मिलियन से अधिक बालिकाओं के बाल-ववाह का खतरा बढ़ गया है।

## बाल-ववाह से संबंधित प्रमुख कारक क्या हैं?

- आर्थिक कारक: गरीबी में जीवनयापन करने वाले परिवार ववाह को लड़की की ज़िम्मेदारी को उसके पति के परिवार को हस्तांतरित करके अपने आर्थिक बोझ को कम करने के साधन के रूप में देख सकते हैं।
  - कुछ क्षेत्रों में दहेज देने की परंपरा परिवारों को बेटी के उचित आयु पूर्ण होने पर दहेज लागत से बचने के लिये कम उम्र में बेटियों का ववाह करने के लिये प्रभावित कर सकती है।
  - इसके अतिरिक्त **प्राकृतिक आपदाओं अथवा कृषि संकट** से ग्रस्त क्षेत्रों में आर्थिक कठिनाइयों का सामना करने वाले परिवार इस समस्या का सामना करने अथवा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिये शीघ्र ववाह का विकल्प चुन सकते हैं।
- सामाजिक मानदंड और पारंपरिक प्रथाएँ: लंबे समय से चली आ रहे रीति-रिवाज और परंपराएँ अक्सर एक सामाजिक आदर्श के रूप में कम उम्र में ववाह को प्राथमिकता देती हैं, जो पीढ़ियों तक इस प्रथा को कायम रखता है।
  - समुदाय या परिवार की ओर से प्रचलित रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुरूप दबाव डालने के कारण विशेषकर लड़कियों का ववाह जल्दी हो जाता है।
- लैंगिक असमानता एवं भेदभाव: लड़कों की तुलना में लड़कियों की बढ़े होने की क्षमता कम उम्र में ववाह में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
  - जो परिवार कम उम्र में शादी को अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के साधन के रूप में देखते हैं, वे अक्सर अपनी बेटियों के लिये शिक्षा और कैरियर में उन्नति के पारंपरिक तरीकों की बजाय इसे चुनते हैं।

## नोट:

**यूनसिफ** बाल ववाह को लड़कियों और लड़कों दोनों के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव के कारण मानवाधिकार उल्लंघन के रूप में वर्गीकृत करता है।

- **सतत विकास लक्ष्य 5.3** में कहा गया है कि वर्ष 2030 तक लैंगिक समानता और महिलाओं एवं लड़कियों के सशक्तीकरण के लक्ष्य के साथ सतत विकास लक्ष्य 5 को प्राप्त करने में बाल ववाह उन्मूलन महत्त्वपूर्ण है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, वर्ष 2022 में दुनिया भर में 5 में से 1 लड़की (19%) की शादी बचपन में ही कर दी गई।

## भारत में बाल ववाह से संबंधित वधायी ढाँचा और पहल क्या हैं?

- **वैधानिक ढाँचा:** भारत ने 2006 में **बाल ववाह नषिध अधिनियम** लागू किया, जिसमें पुरुषों के लिये ववाह की कानूनी उम्र 21 वर्ष और महिलाओं के लिये 18 वर्ष निर्धारित की गई।
  - बाल ववाह नषिध अधिनियम की धारा 16 राज्य सरकारों को वशिष्ट क्षेत्रों के लिये 'बाल ववाह नषिध अधिकारी (CMPO)' नियुक्त करने की अनुमति देती है।
    - CMPO बाल ववाह को रोकने, अभियोजन के लिये साक्ष्य एकत्र करने, ऐसे ववाहों को बढ़ावा देने या सहायता के खिलाफ परामर्श देने, उनके हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समुदायों को संवेदनशील बनाने के लिये ज़िम्मेदार है।
  - सरकार ने महिलाओं की शादी की उम्र को पुरुषों के बराबर करने के लिये इसे 21 साल करने के लिये 'बाल ववाह नषिध (संशोधन) अधिनियम, 2021' नाम से एक अधिनियम पेश किया है।
- **संबंधित पहल:**
  - धनलक्ष्मी योजना: यह बीमा कवरेज वाली बालिका के लिये एक सशर्त नकद हस्तांतरण योजना है।
    - इसका उद्देश्य माता-पिता को चिकित्सा खर्चों के लिये बीमा कवरेज की पेशकश और लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित कर बाल ववाह प्रथा को खत्म करना है।
  - **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (BBBP)** जैसी योजनाओं का उद्देश्य लड़कियों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना एवं बाल ववाह को हतोत्साहित करना है।

## नोट:

ओडिशा सरकार ने बाल विवाह से निपटने के लिये एक व्यापक रणनीति तैयार की है। इसमें लड़कियों की स्कूल में उपस्थिति और गाँव में उपस्थिति पर नज़र रखी जाती है तथा 10-19 वर्ष की लड़कियों के लिये "अद्विका" मंच का प्रयोग किया जाता है।

- कमजोर जनजातीय समूहों को प्रोत्साहन के साथ गाँवों को बाल विवाह मुक्त घोषित करने के लिये दशिया-नरिदेश मौजूद हैं।
- ज़िले विभिन्न दृष्टिकोण लागू करते हैं, जैसे- लड़कियों का डेटाबेस बनाए रखना और [विवाह में आधार संख्या](#) अनिवार्य करना।

## आगे की राह

- **आर्थिक सशक्तीकरण पहल:** जोखिमपूर्ण स्थिति वाली लड़कियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण और उद्यमिता के अवसर प्रदान करना, शीघ्र विवाह के लिये व्यवहार्य विकल्प प्रदान करना चाहिये।
  - परिवारों के लिये सूक्ष्म ऋण तक पहुँच को सुविधाजनक बनाने, आय सृजन को प्रोत्साहित करने और कम उम्र में विवाह के लिये वित्तीय दबाव को कम करने की आवश्यकता है।
- **कला और मीडिया के माध्यम से सामुदायिक जुड़ाव:** बाल विवाह के परिणामों को लेकर जागरूक करने और शक्ति प्रदान करने के लिये कला-आधारित कार्यशालाएँ, थिएटर प्रदर्शन या सामुदायिक कथा सत्र आयोजित करने की आवश्यकता है।
  - संगीत, नुककड़ नाटक या लघु फ़िल्मों के माध्यम से प्रभावी ढंग से अभियानों के संचालन के लिये स्थानीय कलाकारों और प्रभावशाली लोगों के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है।
- **सहकर्मी शिक्षा और परामर्श कार्यक्रम:** युवा नेताओं को बाल विवाह के विरुद्ध वकालत करने के लिये प्रशिक्षित करने, उन्हें अपने समुदायों के भीतर साथियों को शिक्षित करने और सलाह देने हेतु सशक्त करने की आवश्यकता है।
  - स्कूलों में व्यापक शिक्षा मॉड्यूल पेश करने, छात्रों के बीच चर्चा और जागरूकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. राष्ट्रीय बाल नीतिके मुख्य प्रावधानों का परीक्षण कीजिये तथा इसके कार्यान्वयन की स्थितिकी वविचना कीजिये। (2016)

## स्वच्छता प्रणाली

प्रलिमिंस के लिये :

स्वच्छता प्रणालियाँ, [ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियाँ](#), ट्वनि पटि और सेप्टिकि टैंक, शहरी सीवर प्रणालियाँ, [मल कीचड़ उपचार संयंत्र \(FSTPs\)](#)

मेन्स के लिये :

स्वच्छता प्रणालियाँ, सरकारी नीतियाँ और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिये हस्तक्षेप एवं उनके प्रारूप तथा कार्यान्वयन से उत्पन्न होने वाले मुद्दे

[स्रोत: द हट्टि](#)

## चर्चा में क्यों?

उपयोग किया गया पानी जो ज़मीन, खुली जगह, नालियों या नहरों में प्रवाहित होता है, उसे सार्वजनिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के लिये उचित स्वच्छता प्रणालियों में प्रवाहित किया जाना चाहिये।

- सर्वप्रथम स्वच्छता की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व के आसपास प्राचीन सभ्यताओं द्वारा की गई थी, जबकि आधुनिक स्वच्छता प्रणाली वर्ष 1800 के आसपास लंदन में बनाई गई थी।

## स्वच्छता प्रणालियों के प्रकार क्या हैं?

### ■ ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियाँ (OSS):

- ट्वनि पटि, सेप्टिक टैंक, बायो-डाइजेस्टर शौचालय, बायो-टैंक और यूरनि डायवर्जन शुष्क शौचालय ग्रामीण या वशाल शहरी सेटगिस में प्रचलति **ऑन-साइट स्वच्छता प्रणालियाँ (OSS)** के रूप में काम करते हैं। ये प्रणालियाँ अलग-अलग स्थानिक बाधाओं को दूर करते हुए मल कीचड़ या सेप्टेज युक्त उपयोग कथि गए पानी का नषिक्रयि रूप से उपचार करती हैं।
- ट्वनि पटि (गड्डे) और सेप्टिक टैंक:
  - ट्वनि पटिस कार्यक्षमता: इसमें एक-एक करके उपयोग कथि जाने वाले ट्वनि पटिस होते हैं, जुडवाँ गड्डे तरल पदार्थ को ज़मीन में सोखने की सुवधि प्रदान करते हैं, जबकि ठोस पदार्थ जम जाते हैं और नषट हो जाते हैं।
    - एक पटिस दो साल तक नषिक्रयि रहता है, जसिसे पुनः उपयोग के लथि रोगजनक मुक्त सामग्री सुनश्चिति होती है, लेकिन यह चट्टानी मटिटी के लथि अनुपयुक्त होता है।
  - सेप्टिक टैंक संचालन: सेप्टिक टैंक जलरोधक होते हैं; जैसे ही इसतेमाल कथि हुआ पानी टैंक से बहता है, ठोस पदार्थ नीचे बैठ जाते हैं, जबकि मैल- अधिकतर तेल और गरीस ऊपर तैरता रहता है।
    - जबकि सेप्टिक टैंक में जमे हुए ठोस पदार्थ समय के साथ अपघटति हो जाते हैं, जमा हुए मल-कीचड़ और मैल को नियमति अंतराल पर हटाय़ा जाना चाहयि।
    - यह काम वैक्यूम पंपों से सुसज्जति टरकों का उपयोग करके कथि जाता है जो मल कीचड़ को नषिकासति करते हैं और इसे **मल कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP)** नामक उपचार सुवधियाँ तक पहुँचाते हैं।

### ■ शहरी सीवर प्रणाली:

- घनी आबादी वाले शहरी क्षेत्नों में, जहाँ प्रोपर्टीज़ के भीतर जगह की कमी है, पाइपों का एक भूमगित नेटवर्क, जसि सीवर भी कहा जाता है, उपयोग कथि गए जल को एकत्र करता है और उपचार सुवधियाँ तक पहुँचाता है।
- आपस में जुड़े पाइपों का यह नेटवर्क उपयोग कथि गए पानी को शौचालयों, स्नानघरों, रसोई से गुरुत्वाकर्षण द्वारा या पंपों की मदद से उपचार सुवधियाँ तक पहुँचाता है। सीवरों में रख-रखाव और रुकावटों को दूर करने के लथि मशीन-होल्स होते हैं।
- यह प्रयुक्त जल, जसि सीवेज कहा जाता है, सीवर द्वारा **सीवेज उपचार संयंत्रों (STP)** तक पहुँचाया जाता है।

## उपचार सुवधियाँ के क्या कार्य हैं?

### ■ मल कीचड़ उपचार संयंत्र (FSTP):

- **FSTP की कसिमें:** FSTP या तो यांत्रिक (स्क्रू प्रेस जैसे उपकरण का उपयोग करके) या गुरुत्वाकर्षण-आधारति ससि्टम (रेत सुखाने वाले बेड का उपयोग करके) में कार्य करते हैं। ये सुवधियाँ प्रभावी रोकथाम, परविहन और उपचार के उद्देश्य से मल कीचड़ का प्रबंधन करती हैं, जसि प्रायः **मल कीचड़ प्रबंधन (FSM)** के रूप में जाना जाता है।
  - छोटे शहरों अथवा ग्रामों में **OSS-FSM** प्रचलति है।
- पुनः उपयोग तथा नषिटान: FSTPs से उपचारति ठोस पदार्थ को जैविकि नगरपालिका अपशषिट के साथ मशिरति कर खाद नरिमति हो सकती है जो कृषि में पुनः प्रयोज्य के रूप में कार्य करती है।
  - उपचारति जल को अमूमन FSTP परसिर के भीतर भूनरिमाण के लथि पुनः उपयोग कथि जाता है, जो एक सतत् दृषटकिण को उजागर करता है।

### ■ वाहति मल उपचार संयंत्र (STPs):

- व्यापक जल उपचार: STPs उपयोग कथि गए जल से प्रदूषकों को नषट करने के लथि भौतिकि, जैविकि एवं रासायनिकि प्रक्रथियाओं को नथिोजति करते हैं।
  - FSTPs के समान इसके प्राथमिकि चरण में ठोस पदार्थों को अलग कथि जाता है तथा इसके बाद शुद्धकिरण होता है जहाँ सूक्ष्मजीव ठोस पदार्थों को समाप्त करते हैं जसिसे अंततः कीटाणुशोधन होता है।
- उन्नत तकनीकें तथा बभिन्न प्रकार: उन्नत STPs जल के पुनः उपयोग को बढ़ाने के लथि झिल्ली नसिंधन (Membrane Filtration) जैसी बधियाँ का उपयोग करते हैं।
  - ये सुवधियाँ यंत्रिक तथा गैर-यंत्रिक प्रकारों में उपलब्ध हैं, जनिका चयन शहर प्रशासन की तकनीकी तथा वत्तिथि क्षमताओं के आधार पर कथि जाता है।

**नोट:** FSTPs छोटे होते हैं तथा **ठोस अपशषिट प्रबंधन** साइटों के साथ नथिोजति कथि जा सकते हैं अथवा कीचड़ स्रोतों के समीप स्थापति कथि जा सकते हैं। इसके वषिरीत STPs बड़ी, केंद्रीकृत सुवधियाँ हैं जो संपूर्ण समुदायों अथवा शहरी क्षेत्नों में उपयोग की जाती हैं तथा अमूमन उपचारति जल के नरि्वहन के लथि जल नकियाँ के समीप स्थति होती हैं।

## ऐसी जटलि स्वच्छता प्रणाली की क्या आवश्यकता है?

- जैसे-जैसे पानी अपने बभिन्न घरेलू और गैर-घरेलू उपयोगों के माध्यम से आगे बढ़ता है, यह प्राकृतिक तथा साथ ही मानव-नरिमति अशुद्धथियों को जमा करता है जसिमें कार्बनिक पदार्थ, डटिरजेंट से पोषक तत्त्व, बैकटीरथिया, वायरस, परजीवी जैसे रोगजनक, सॉल्वेंट्स एवं कीटनाशकों से लेकर भारी धातुएँ शामिल हैं। इसमें मटिटी, मलबा, खनजि व लवण जैसे ठोस पदार्थ भी शामिल हैं।
- यह सुनश्चिति करने के लथि कि उपयोग कथि गया पानी प्राकृतिक वातावरण में पुनः शामिल होने पर इन अशुद्धथियों के परिणामस्वरूप प्रदूषति या सार्वजनिकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का कारण नहीं बनता है, **उपयोग कथि गए पानी का नषिटान या पुनः उपयोग करने से पहले उसमें शामिल प्रदूषकों को हटाना और उसका उपचार करना आवश्यक है।**

- स्वच्छता के प्राथमिक प्रेरक हमेशा **गंध और सौंदर्यशास्त्र** रहे हैं, लेकिन जब तक सार्वजनिक तथा पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ उनका संबंध स्पष्ट नहीं हुआ तब तक लोगों को यह एहसास नहीं हुआ कि "आउट ऑफ साइट" दृष्टिकोण का उपयोग करना अपर्याप्त था।

## नषिकर्ष:

- स्वच्छता प्रणालियों के आविष्कार के बाद से सार्वजनिक स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण सुधार हुआ है, लेकिन सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुँच एक चुनौती बनी हुई है।
- खराब डिजाइन पर निर्मित प्रणाली और असुरक्षित संचालन तथा रखरखाव प्रथाओं जैसे मुद्दों का समाधान उपयोग किये गए पानी के प्रभावी ढंग से प्रबंधन एवं हमारे मूल्यवान जल निकायों व भूजल जलभृतों की रक्षा के लिये महत्वपूर्ण है।

## डकिडगि गुड गवर्नेंस

### प्रलिमिस के लिये:

[अटल बहारी वाजपेयी](#) और [सुशासन दविस](#), [वशिव बैंक](#), भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक 2022, [केंद्रीय लोक शकियत नविवरण और नगिरानी प्रणाली](#), [सूचना का अधिकार अधिनियम](#), [73वाँ और 74वाँ सांविधानिक संशोधन](#), [यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस](#), [आकांक्षी ज़िला कार्यक्रम](#), नागरिक चार्टर

### मेन्स के लिये:

भारत में शासन व्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दे, भारत में सुशासन से संबंधित प्रमुख पहल

[सरोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

## चर्चा में क्यों?

25 दिसंबर को भारत ने पूर्व प्रधानमंत्री [अटल बहारी वाजपेयी](#) की जयंती के अवसर पर [सुशासन दविस](#) मनाया।

- वार्षिक तौर पर मनाया जाने वाला यह दविस शासन व्यवस्था तथा सरकारी प्रक्रियाओं में उत्तरदायित्व के संबंध में नागरिक जागरूकता बढ़ाने का प्रयास करता है।
- इस अवसर पर एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण (Integrated Government Online Training- iGOT) कार्यक्रमों प्लेटफॉर्म पर तीन नई सुविधाओं, [माई iGOT](#), [ब्लेंडेड प्रोग्राम](#) और [क्यूरेटेड प्रोग्राम](#) का शुभारंभ किया गया।

## सुशासन क्या है?

- **परिचय:**
  - शासन व्यवस्था उन प्रक्रियाओं, प्रणालियों तथा संरचनाओं को संदर्भित करती है जिनके माध्यम से संगठनों, समाजों अथवा समूहों को **नरिदेशित, नयित्तरति एवं प्रबंधित** किया जाता है।
    - सुशासन को मूल्यों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके माध्यम से एकसार्वजनिक संस्थान सार्वजनिक मामलों का संचालन करती है तथा सार्वजनिक संसाधनों का प्रबंधन इस तरह से करती है जो मानवाधिकारों, वधि सम्मत शासन एवं समाज की ज़रूरतों के अनुरूप हो।
    - **वशिव बैंक** सुशासन को उन परंपराओं तथा संस्थानों के संदर्भ में परिभाषित करता है जिनके द्वारा कसिी देश में प्राधिकार का प्रयोग किया जाता है। इनमें शामिल हैं:
      - वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सरकारों का चयन, नगिरानी तथा प्रतसि्थापन किया जाता है।
      - प्रभावी नीतियों को प्रभावी ढंग से तैयार कर उन्हें कार्यान्वित करने की सरकार की क्षमता।
      - उन संस्थानों के प्रतनिगरिकों तथा राज्य का सम्मान जो उनके बीच आर्थिक एवं सामाजिक संबंधों को नयित्तरति करते हैं।

सुशासन के मूल सिद्धांत:



## वश्वव्यापी शासन संकेतक क्या है?

- वश्व बैंक की वश्वव्यापी शासन संकेतक परयोजना शासन के छह मूलभूत उपायों के आधार पर 200 से अधिक देशों का मूल्यांकन करती है।
- छह संकेतक हैं:
  - अभवियक्ति और दायित्व
  - राजनीतिक स्थरिता और हसिा का अभाव
  - सरकारी प्रभावशीलता
  - नयामक गुणवत्ता
  - [वधि का शासन](#)
  - भ्रष्टाचार पर नयित्रण

## भारत में शासन से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- भ्रष्टाचार और नौकरशाही अक्षमता: [भ्रष्टाचार बोध सूचकांक- 2022](#) में रश्वतखोरी और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के बारे में चर्चाओं को उजागर करते हुए भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर था।
- असमानता और सामाजिक बहिष्कार: आर्थिक विकास के बावजूद, अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ा अंतर बना हुआ है। वर्ष 2022 की ऑक्सफैम रिपोर्ट से पता चला है कि भारत में सबसे अमीर 1% लोगों के पास देश की 40% से अधिक संपत्ति है, जबकि निम्न स्तरीय 50% के पास सरिफ 3% संपत्ति है। इससे स्वास्थय देखभाल, शक्तिषा और अवसरों तक पहुँच में असमानताएँ बढ़ती हैं।
- नीतियों और योजनाओं का अप्रभावी कार्यान्वयन: कई अच्छे इरादे वाले सरकारी कार्यक्रम खराब नषिपादन के कारण प्रभावित होते हैं, जिससे उनका प्रभाव सीमित हो जाता है।
  - वर्ष 2023 में CAG ने [आयुषमान भारत योजना](#) में अनयिमतिताएँ पाईं, इसके अलावा CAG की एक अन्य रिपोर्ट में [झारखंड में पुरुषों को वधिवा पेंशन के हसत्तांतरण](#) पर प्रकाश डाला गया है।
- अपर्याप्त न्यायिक अवसंरचना: भारत के न्यायालय बड़े पैमाने पर लंबित मामलों के बोझ से दबे हुए हैं, जिससे वविाद समाधान और न्याय तक पहुँच में देरी हो रही है, खासकर हाशयि पर रहने वाले लोगों को।

- वर्ष 2023 में [सर्वोच्च न्यायालय](#) में 80,000 से अधिक मामले लंबित थे, जिससे कानूनी सहायता तक समय पर पहुँच को लेकर चर्चाएँ बढ़ गईं।
- **पर्यावरणीय गतिरोध और जलवायु परिवर्तन:** भारत को वायु प्रदूषण, जल की कमी और वनों की कटाई जैसी प्रमुख चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। [वर्ष 2023 की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट](#) ने पर्यावरणीय नयियों के कमजोर प्रवर्तन को उजागर करते हुए **कई भारतीय शहरों को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहरों में स्थान दिया है।**
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण और जवाबदेही का अभाव:** बढ़ते पक्षपात और चुनावी लाभ पर ध्यान कभी-कभी भारत में दीर्घकालिक नीति नियोजन और लोक कल्याण पर भारी पड़ जाता है।

## भारत में सुशासन से संबंधित प्रमुख पहल क्या हैं?

- **पारदर्शिता और दायित्व:**
  - [सूचना का अधिकार अधिनियम \(2005\)](#): यह अधिनियम नागरिकों को सरकारी जानकारी तक पहुँचने, पारदर्शिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार को कम करने का अधिकार देता है।
  - [केंद्रीय लोक शिकायत निवारण और नगरानी प्रणाली \(CPGRAMS\)](#): सरकारी विभागों के खिलाफ शिकायतें दर्ज करने और उन पर नज़र रखने के लिये ऑनलाइन मंच।
  - [ई-गवर्नेंस पहल](#): बढ़ी हुई दक्षता और कम मानवीय संपर्क के लिये सरकारी सेवाओं (जैसे, ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग, संपत्ति पंजीकरण) का डिजिटलीकरण।
  - [सटीक चार्टर](#): सरकारी एजेंसियों द्वारा सेवा मानकों और समय-सीमा के प्रति प्रतिबद्धता, जवाबदेही बढ़ाना।
- **नागरिक भागीदारी और सशक्तीकरण:**
  - [MyGov प्लेटफॉर्म](#): यह नागरिकों को नीतिगत चर्चाओं में भाग लेने, विचार प्रस्तुत करने और सरकार को प्रतिक्रिया प्रदान करने में सक्षम बनाता है।
  - [ग्राम सभाएँ](#): ग्रामीण क्षेत्रों में सहभागी निर्णय लेने के लिये ग्राम-स्तरीय बैठकें।
  - [शिक्षा का अधिकार अधिनियम \(2009\)](#): समुदायों को सशक्त बनाते हुए 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिये मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करता है।
- **वर्केंद्रीकरण और स्थानीय शासन:**
  - [73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन](#): स्थानीय लोकतंत्र को बढ़ावा देते हुए वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के साथ पंचायतों (ग्राम परिषदों) तथा नगर पालिकाओं को सशक्त बनाना।
  - [आकांक्षी जिला कार्यक्रम](#): भौगोलिक रूप से वंचित 112 जिलों में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - [स्मार्ट सटी मशिन](#): बेहतर जीवन के लिये बुनियादी ढाँचे और प्रौद्योगिकी समाधान के साथ 100 शहरों का विकास।
- **अन्य पहल:**
  - [डिजिटल इंडिया कार्यक्रम](#): इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी तक व्यापक पहुँच के साथ भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज में बदलना है।
  - [प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण](#): बैंक खातों के माध्यम से सीधे लाभार्थियों को सब्सिडी और लाभ का हस्तांतरण, रसिद और भ्रष्टाचार को कम करना।
  - [आधार कार्ड](#): नागरिकों के लिये विशिष्ट पहचान प्रणाली, वित्तीय समावेशन और सेवा वितरण को बढ़ावा देना।
  - [दवाला और दवालापन संहिता \(2016\)](#): यह खराब ऋण की समस्या को हल करने और व्यापार पुनरुद्धार की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करती है।
  - [यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस \(UPI\)](#): भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नगिम (NPCI) द्वारा विकसित त्वरित वास्तविक समय मोबाइल भुगतान प्रणाली।
    - यह एकल मोबाइल एप का उपयोग करके नरिबाध अंतर-बैंक लेन-देन सक्षम बनाता है।

## आगे की राह

- **जनडेटा प्लेटफॉर्म: वैयक्तिकृत सेवाओं और नीतिगत निर्णयों में नागरिकों की प्रत्यक्ष भागीदारी के लिये** ब्लॉकचेन तकनीक द्वारा समर्थित एक सुरक्षित डेटा प्लेटफॉर्म बनाए जाने की आवश्यकता।
  - इसमें [स्मार्ट गवर्नेंस डैशबोर्ड](#), विभिन्न सरकारी विभागों के लिये प्रमुख पहल की पारदर्शिता और पहुँच को बढ़ावा देना शामिल होना चाहिये।
- **नौकरशाही में सुधार: प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना, लालफीताशाही को कम करना** और सार्वजनिक सेवा के भीतर व्यावसायिकता तथा जवाबदेही को बढ़ाना भी महत्वपूर्ण है। **विकास (वेरिबल एंड इमर्सिवि कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट) इस दशा में एक आवश्यक कदम होगा।**
- **त्वरित न्यायिक सुधार:** लंबित मामलों का समाधान करके न्यायालय प्रणाली के भीतर बुनियादी ढाँचे और दक्षता में सुधार करना और सभी के लिये न्याय तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करना। [ई-कोर्ट](#) और [अदालती कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग](#) इस दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- **AI-संचालित शिकायत समाधान:** एक AI संचालित प्रणाली विकसित करना जो सार्वजनिक शिकायतों का विश्लेषण, पैटर्न की पहचान करती है और स्वचालित रूप से उन्हें त्वरित समाधान के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करती है।



- नागरिक सहभागिता की पुनः कल्पना: शहरी स्थानीय निकायों और पंचायतों की देख-रेख में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में समुदाय-आधारित नवाचार प्रयोगशालाएँ स्थापित करना, नागरिकों को सरकारी एजेंसियों के सहयोग से स्थानीय समस्याओं का स्थानीय समाधान खोजने के लिये सशक्त बनाना।
- भविष्योन्मुखी शिक्षा पाठ्यक्रम: आलोचनात्मक सोच, डिजिटल साक्षरता और डेटा विश्लेषण जैसे कौशल को शिक्षा प्रणाली में एकीकृत करना, भविष्य की पीढ़ियों को प्रौद्योगिकी-संचालित शासन परदृश्य में सक्रिय भागीदारी के लिये तैयार करना।

इसलिये **भारत को सतत विकास लक्ष्य (SDG) 16: शांति, न्याय और मज़बूत संस्थानों के साथ संरेखित** करते हुए "न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन" के सिद्धांत का पालन करना चाहिये।

## अटल बहारी वाजपेयी:



- 25 दिसंबर, 1924 को ग्वालियर, जो अब मध्य प्रदेश का हिस्सा है, में जन्मे अटल बहारी वाजपेयी ने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीति में प्रवेश किया।
- 1996 और 1999 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार जनादेश हासिल करने वाले पहले व्यक्ति बने। (वर्तमान में नरेन्द्र मोदी)
  - 9 लोकसभा और 2 राज्यसभा चुनाव जीते, 1994 में भारत के 'सर्वश्रेष्ठ सांसद' का खिताब अर्जित किया।
- 1994 में पद्म विभूषण प्राप्त हुआ और 2015 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. विभिन्न स्तरों पर सरकारी तंत्र की प्रभावशीलता और शासन तंत्र में जनसहभागिता अन्यायनाश्रति होती है। भारत के संदर्भ में इनके बीच संबंध पर चर्चा कीजिये। (2016)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/27-12-2023/print>

